IJAER/June-July 2013 /Volume-02/Issue 4 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

भारत की गरीबी और उदारीकरण नीति विश्लेषण

डॉ बाबू लाल मीणा

व्याख्याता.राज. विज्ञान

राजकीय कन्या महाविद्यालय .अजमेर

सार

नियोजित विकास वेफ चालीस वर्षों वेफ बाद, भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार तथा खाद्यन्नों वेफ उत्पादन में स्व–निर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इसवेफ बावजूद, जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका वेफ लिए कृषि पर निर्भर है। 1991 में, भुगतान संकट वेफ कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रापात हुआ। इस इकाई में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत वेफ संदर्भ में उनवेफ प्रयोग का मूल्यांकन किया गया है।

मुख्य शब्द : *गरीबी, उदारीकरण नीति*

परिचय

आपने पिछले अध्याय में प चे को अपनाया। इसमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं वेफ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ एक साथ थीं। वुफछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था वेफ नियमन और नियंत्राण वेफ लिए इतने अधिक नियम–कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक संवृ(और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरु(हो गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसने अपनी विकास–यात्राा लगभग गतिहीनता वेफ स्तर से वही आरंभ की थी, जो बचत में संवृ(और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। साथ ही, कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धिद्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है।

वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ट्टणों वेफ मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ट्टण वेफ भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं वेफ आयात वेफ लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिशर्व पंद्रह दिनों वेफ लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धिने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने वुफछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रण–नीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था वेफ विभिन्न क्षेत्राकों पर उन नीतियों वेफ प्रभावों पर विचार करेंगे।

पृष्ठभूमि

इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 वेफ दशक में अर्थव्यवस्था में अवुफशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों वेफ क्रियान्वयन वेफ लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि वेफ माध्यम से पफंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि वेफ आयात वेफ लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन वेफ निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं।

इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्पफोट वेफ कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय वेफ कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्राों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्राों से किसी शीघ्र प्रतिपफल की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच–विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति वेफ लिये सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया।

इस प्रकार वेफ अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़तेआयात वेफ लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया।

उदारीकरण

हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों वेफ नियमन वेफ लिए बनाए गए नियम–कानून ही संवृ(और विकास वेफ मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था वेफ विभिन्न क्षेत्राों को ‘मुक्त’ करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात–निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 वेफ दशक में भी आरंभ किए गए थे। ¯कतु, 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थीं। आइए, हम वुफछ महत्वपूर्ण क्षेत्राों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्रा हैं–औद्योगिक क्षेत्राक, वित्तीय क्षेत्राक, कर–सुधार, विदेशी विनिमय बाशार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्राक, जिनपर 1991 में तथा 1991 वेफ बाद से विशेष ध्यान दिया गया था।

औद्योगिक क्षेत्राक का विनियमीकरण : भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था ;कद्ध सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक पफर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादनकी मात्राा का निर्धारण करने वेफ लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी(ख) अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था(ग) कुछ वस्तुओं का उत्पादन वेफवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को वुफछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों वेफ निर्धारण तथा वितरण वेफ बारे में भी अनेक नियंत्राणों का पालन करना पड़ता था।

1991 वेफ बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्पफोटकों, इलेक्ट्रोनिकी, विमानन तथा औषधि–भेषजत्र्ञ इन छः उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों वेफ लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्राक वेफ लिए सुरक्षित उद्योगों में भी वेफवल वुफछ मुख्य गतिविध्याँ, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अध्किांश वस्तुएँ भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं। अनेक उद्योगों में अब बाशार को कीमतों वेफ निर्धारण की अनुमति मिल गई है।

वित्तीय क्षेत्राक सुधार : वित्त वेफ क्षेत्राक में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाशार जैसी वित्तीय संस्थाएँ सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्राक का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक वेफ विभिन्न नियम और कसौटियों वेफ माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों वेफ कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमारख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्राकों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्राक सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्राक वेफ नियंत्राक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्राक वेफ एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्राक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रा हो जाएगा।

कर व्यवस्था में सुधार : इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियाँ भी कहा जाता है। करों वेफ दो प्रकार होते हैं: प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों वेफ लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 वेफ बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसवेफ पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों वेफ कारण ही कर–वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊँची नहीं हों, तो बचतों को बे राष्ट्रीय स्तर वेफ बाशार की रचना की जा सवेफ। वर्ष 2013 में, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम–2013 ;जी. एस. टी. –2016) कानून को पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2013 से लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर–वंचन कम होने की तथा 'एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार' का निर्माण होने की आशा है। करदाताओं वेफ द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने वेफ लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, साथ ही, कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है।

विदेशी विनिमय सुधार: विदेशी क्षेत्राक में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाशार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या वेफ तत्कालिक निदान वेफ लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा वेफ आगमन में वृ(हुई। इसवेफ अंतर्गत विदेशी विनिमय बाशार में रुपये वेफ मूल्य वेफ निर्धारण को भी सरकारी नियंत्राण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाशार ही विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति वेफ आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है।

निजीकरण

इसका तात्पर्य है, किसी सार्वजनिक उपक्रम वेफ स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियाँ निजी क्षेत्राक की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं: (क) सरकार का सार्वजनिक कंपनी वेफ स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा (ख) सार्वजनिक क्षेत्राक की कपंनियों को सीधे बेच दिया जाना।

किसी सार्वजनिक क्षेत्राक वेफ उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री वेफ माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार वेफ अनुसार, इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ावामिलेगा।

सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यवुफशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण वेफ लिए, वुफछ सार्वजनिक उपक्रमों को 'महारत्न', 'नवरत्न' और 'लघुरत्न' का विशेष दर्जा दिया गया है।

वैश्वीकरण

यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था वेफ साथ एकीकरण वेफ रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है, जिनवफा उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसवेफ अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं वेफ अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्राों की रचना का प्रयास है, जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं वेफ प्रभाव भारत वेफ घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमामुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है।

बाह्य प्रापण : वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट् परिणाम है। इसमें कंपनियाँ किसी बाहरी स्रोत ;संस्थाद्ध से नियमित सेवाएँ प्राप्त करती हैं, जिन्हें पहले देश वेफ भीतर ही प्रदान किया जाता था जैसे कि कानूनी सलाह, वंफप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। संचार वेफ माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी वेफ प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण, विदेशों से इन सेवाओं को

प्राप्त करने ;बाहय प्रापणद्ध की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएँ, संगीत की रिकॉर्डिंग, पिफल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों वेफ सुपुर्द किया जाने लगा है।

अनेक विकसित देशों की कंपनियाँ भारत की छोटी–छोटी संस्थाओं से ये सेवाएँ प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों वेफ माध्यमों जैसे, इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत शून्य से नौ तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों वेफ बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों वेफ साथ–साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियाँ भारत से ये सेवाएँ प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह वेफ कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा वुफशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय 'बाह्य प्रापण' का एक गंतव्य बना दिया है।

विश्व व्यापार संगठनः व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि ;ळ।ज्ज्द्ध वेफ परवर्ती विश्व व्यापार संगठन ॅ;ज्व्द्ध का गठन 1995 में किया गया। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक वेफ रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है, जिसमें कोई देश मनमानेढंगसे व्यापार वेफ मार्ग में बाधाएँ खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही, इसका ध्येय सेवाओं वेफ सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व वेफ संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सवेफ। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं वेफ साथ–साथ सेवाओं वेफ विनिमय को भी स्थान दिया गया है। ऐसा सभी सदस्य देशों वेफ प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर तथा अपने बाशारों को सदस्य देशों वेफ लिए खोलकर किया गया है।

सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्थाएक समीक्षा

अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए तीन दशक हो चुवेफ हैं। आइए, इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था वेफ निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। सारणी 3.1 को देखें। 1991 वेफ बाद से भारत में दो दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धिहोती रही। सकल घरेलू उत्पाद 1980–91 में 5.6 प्रतिशत से बढ़ कर 2007–2012 में 8.2 प्रतिशत हो गई। आर्थिक सुधरों की अवध् िमें कृषि की वृद्धि में कमी आयी। जहाँ औद्योगिक क्षेत्राक में उतार–चढाव हुए, वहीं सेवा क्षेत्राक में वृद्धि बढगई। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा–क्षेत्राक में वृद्धिवेफ कारण हुई है। 2012–13 कीअवध् िमें विभिन्न क्षेत्राकों में 1991 वेफ बाद से होने वाली वृद्धिदरों में रुकावट आयी। जहाँ 2012–13 में कृषि की वृद्धिदर में बढोतरी आयी, वहीं बाद के वर्षों में इस क्षेत्राक की वृद्धिदरणात्मक हो गई। सेवा क्षेत्राक में ऊँची वृद्धि दर बनी रही, जो 2012–13 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धिसे भी अध्कि थी। इस क्षेत्राक में अबतक का उच्च वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत रेकार्ड किया गया। औद्योगिक क्षेत्राक में 2012–13 में तेज गिरावट आई, तत्पश्चात् बाद बाद वर्षों में बढने लगा।

अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश तथा विदेशी विनिमय रिज़र्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश (जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं) 1990–91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2012–13 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। भारत के विनिमय रिज़र्व का आकार भी 1990–91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2012–13 में 413 बिलियन डॉलर हो गया है। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिज़र्व का सातवाँ सबसे बड़ा धारक माना जाता है।

1991 के बाद से भारत वाहन, कल–पु दवा का सामान, इंजीनियरी उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रादि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाज़ार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है।

दूसरी ओर, सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। ये समस्याएँ विशेषकर रोजगारसृजन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हैं।

संवृद्धि और रोजगार यद्यपि सकल:घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित संवृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार और संवृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर्संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझाए जाएँगे ।

कृषि में सुधार: सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की संवृद्धि दर कम होती जा रही है।

1991 के बाद से सुधार अवधि में कृषि क्षेत्रक में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात् सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाज़ार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है (ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी) । साथ ही, उर्वरक सहायिकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने वेफ कारण इस क्षेत्राक की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसवेफ कारण भारत वेफ किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिवूफल प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष

उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों वेफ माध्यम से वैश्वीकरण वेफ भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। वुफछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भाँति देखा जाना चाहिए क्योंकि विश्व बाशारों में बेहतर पहुँच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों वेफ बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'महत्वपूर्ण' बनने का अवसर प्रदान कर रहा है।

दूसरी ओर, आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों वेफ आंतरिक बाशारों पर कब्जा करने की साजिश है। इनवेफ अनुसार, वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन् उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाशार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों वेफ बीच की खाई और विस्तृत हो रही है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत वेफ 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। उस संकट वेफ निदान वेफ लिए बाहरी शक्तियों वेफ परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। इन्होंने वेफवल उच्च आयवर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया है तथा सारी संवृ(वुफछ इने–गिने क्षेत्रों तक सीमित रही है। ये क्षेत्रा हैं – दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएँ, भवन निर्माण और व्यापार आदि। कृषि, विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्राक ;जो देश वेफ करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैंद्ध इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं।

संदर्भ:

1ए आचार्य शंकर 2003. इंडियाज इकॉनोमी: सम इश्यूज एंड आनसर्ज, एवेफडेमिक पफाउंडेशन, नयी दिल्ली।

2ण आल्टरनेटिव सर्वे ग्रुप 2005. आल्टरनेटिव इक्नॉमिक सर्वे, इंडिया 2004–05, डिसइक्विलाइजिंग ग्रोथ, दानिश बुक्स दिल्ली।

3ण अहलूवालिया, आई.जे.एंड आठ.एम.डी. लिटिल, 1998. इंडियान इकॉनॉमिक रिपफोर्मस एंड डेवलमंट, ऑक्सपफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली।

4ण बर्धन प्रनव 1998. द पांलिटिकल इकॉनामी ऑपफ डेवलपमेंट इन इंडिया, एक्सपेंडेड एडीसन विथ एन ऐपीलॉग ओन द पॉलिटिकल इकोनोमी ऑपफ रिपफार्म इन इंडिया, ऑक्सपफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

5ण भादुरी अमित और दीपक नायर 1996. द इंटेलिजेंट परसंस गाईड टू लिब्रलाजेशन, पेंग्युइन, दिल्ली। भगवती, जगदीश, 1992. इंडिया इन ट्रांजीशनः प्रफीइंग द इकॉनॉमी ऑक्सपफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रस, दिल्ली।`

6ण बायरस टिरेन्स जे 1997. द स्टेट, डेवेलमेंट प्लानिंग एंड लिब्रलाइजेशन इन इंडिया, ऑक्सपफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

7ण चढा जी.वेफ. 1994. पॉलिसी परसपेक्टिव इन इंडियन इकोनोमिक डेवेलेपमेंट, हर आनंद दिल्ली।

8ण चेलयाह राजा जे. 1996. टूवार्डस ससटेनेबल ग्रोथ, एसयेज इन पिफसकल सेंटर रिपफार्मस इन इंडिया, ऑक्सपफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

9ण देवराय विवेक और राहुल मुखर्जी ;संपादितद्ध 2004. द पॉलिटिकल इकॉनोमी ऑपफ रिपफोर्म्स, बुकवेल पब्लिवेफशन, नई दिल्ली।

10ण ड्रेजी जीन और अमर्त्य सेन 1996. इंडिया इकोनोमिक डेवेलेपमेंट एंड सोशल ऑपरच्यूनिटी, ऑक्सपफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

11ण दत्त रूद्र और वेफ.पी.एस सुन्दरम 2005. इंडियन इकोनामी, एस.चंद एंड कंपनी, नई दिल्ली।